प्ररूप 3 घ

[नियम 16(2) देखिये]

कार्यालय जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति

जिला.....छत्तीसगढ़

आवक क्रमांक..... दिनांक .....

आवेदन पत्र की पावती

(इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जावे तथा उसका प्रतिपर्ण कार्यालय में संधारित किया जावे)

आज दिनांक ..... को श्री/श्रीमती/कुमारी .....

आत्मज/आत्मजा ..... उम्र ..... वर्ष ..... व्यवसाय .....

निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र सत्यापित करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख मूल/अभिप्रमाणित प्रति में प्राप्त हुए है :–

(1) आवेदक अथवा आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित दस्तावेज, जिसमें उसकी जाति अंकित है

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल) ;
(दो) जमाबंदी (सर्वेक्षण) गिरदावरी;
(तीन) राज्य बंदोबस्त;
(चार) अधिकार अभिलेख (1954);
(पांच) जनगणना (1931);
(छः) वन विभाग की जमाबंदी;
(सात) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
(आठ) जन्म या मृत्यु की पंजी;
(नौ) पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में, प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी
(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण प्रमाण–पत्र की प्रति
(ग्यारह) अन्य दस्तावेज जिससे आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति होना प्रमाणित होता है
(बारह) .....

(2) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपियां जिससे यह प्रमाणित हो सके के आवेदक के पूर्वज राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करते थे।

(3) पूर्वजों से प्रारंभ कर आवेदक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।

(4) आवेदक अथवा उसके पिता अथवा उसके वैध पालक का शपथ पत्र प्ररूप 2क के अनुसार (मूल प्रति में)।

(5) दस्तावेज जिनसे दर्शित हो कि आवेदक के पिता राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हैं तथा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिसूचना तिथि को अथवा उसके पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।

(6) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक के पिता का पूर्व वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण–पत्र अथवा फार्म 16 की अभिप्रमाणित प्रति।

(7) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें यथेष्ट डाक टिकट लगी हो।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप 4 क (1)
(नियम 9 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल.....जिला.....छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक .....
सरल क्रमांक..... दिनांक .....

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जाति के लिए)
(हल्के नीले (आसमानी) रंग के कागज में)

एतद्द्वारा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/आत्मजा श्री..... निवास ग्राम .....तहसील.....जिला ....छत्तीसगढ़.....जाति का/की सदस्य है और संविधान के अनुच्छेद 341 के अध्यधीन इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 की तृतीय अनुसूची के अनुक्रमांक .....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति श्री..... अनुसूचित जाति का/की है।

2– यह प्रमाण–पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जॉच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/पदमुद्रा

प्ररूप 4 क (2)
(नियम 9 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
उपखण्ड.....जिला.....छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक .....

दिनांक .....

सरल क्रमांक.....

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जनजाति के लिए)

(हल्के गुलाबी रंग के कागज में)

एतद्द्वारा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/आत्मजा श्री..... निवास ग्राम .....तहसील.....जिला ....छत्तीसगढ़.....जनजाति का/की सदस्य है और संविधान के अनुच्छेद 342 के अध्यधीन इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 20 की तृतीय अनुसूची के अनुक्रमांक .....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति श्री..... अनुसूचित जनजाति का/की है।

2– यह प्रमाण–पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जॉच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/पदमुद्रा

प्ररूप 4 क (3)
(नियम 9 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल.....जिला.....छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक .....
सरल क्रमांक..... दिनांक .....

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
(हल्के पीले रंग के कागज में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/आत्मजा श्री.....
.....निवास ग्राम .....तहसील.....जिला .....छत्तीसगढ़..
.....जाति का/की सदस्य है। इस जाति को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समय–समय पर पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं के द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5/25/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसान्य किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुकमांक .....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पिता/पति श्री.....अन्य पिछड़ा वर्ग का/की है।

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....कीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36012/22/93/स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 8–9–93 यथा संशोधित परिपत्र संख्या 36033/3/2004–स्था (आरक्षण) दिनांक 14–10–2008 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–9–3/2001/1–3 दिनांक 24–6–2009 के कालम 3 में किया गया है

3– यह प्रमाण–पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जॉच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/पदमुद्रा

प्ररूप 4 ख
(नियम 10 देखिए)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

पुस्तक क्रमांक .....
सरल क्रमांक..... दिनांक .....

अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र
(सफेद रंग के कागज में)
(केवल प्राथमिक/माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/अन्य प्रयोजनों की स्वीकृति हेतु मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/आत्मजा श्री..... निवास ग्राम .....तहसील..... .....जिला ....के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार वह .....जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में सम्मिलित नहीं) का/की सदस्य है और संविधान के अनुच्छेद 341/342/राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा इस जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 के अंतर्गत अनुसूची 3/उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची 4/राज्य शासन की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित है और श्री/श्रीमती/कुमारी .....के पिता/पति का नाम .....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की है।

2– प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए .....है।

3– यह प्रमाण–पत्र केवल भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली छात्रवृत्ति/शिष्यवृति को प्राप्त करने के तात्कालिक प्रयोजन के लिए जारी किया गया है और इस प्रमाण–पत्र की वैधता जारी दिनांक से केवल 6 माह अथवा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए है

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

पदमुद्रा(सील)

प्ररूप 4 ग

(नियम 11 देखिए)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल.....जिला.....छत्तीसगढ़

पुस्तक कमांक .....
सरल क्रमांक.....

दिनांक .....

SOCIAL CASTE CERTIFICATE (MIGRANT)

This is to Certify that Shri/Shrimati/Kumari ----------Son/Daughter of ---------- of Village/Town ----------in---------- ----------District/Division ----------of the State/Union Teritory ---- ---------- belongs to the ----------Caste/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe Under :-

1. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
2. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
3. The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories) Order, 1951
4. The Constitution (Scheduled Castes)(Union Teritories) Order, 1951 As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 the Bombay Reorganisation Act, 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.
5. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
6. The Constitution (Andman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
7. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
8. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
9. The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes Order, 1964
10. The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967
11. The Constitution (Goa, Daman And Diu) Scheduled Castes Order, 1968
12. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
13. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
15. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*This Certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribe Certificate issued to Shri/Shrimati/Kumari ----------Son/Daughter of ---------- ---------- of Village/Town ----------in---------- District/Division ----------of the State/Union Teritory ---------- who belong to the ----------Caste/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Teritory ----------issued by the ---------- ----------(name of prescribed authority) vide their no ..... dated ..... and the holder on the certificate is not entitled to any concession/ facilities extended to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes by the Government of Chhattisgarh.

** Shri/Shrimati/Kumari ---------- and or his/her family ordinary reside(s) om village/ town ---------- of ---------- District/ Division of the State of Chhattisgarh.

Signature
Designation
(With seal of Officer)

*Applicable to Migrants only
**Not applicable to Migrants

प्ररूप 4 घ (1)
[नियम 17 (1) देखिये]

दिनांक ....

क्रमांक ....

सत्यापन प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जाति के लिए)
(हल्के नीले (आसमानी) रंग के कागज में)

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा श्री .... निवासी .... तहसील .... जिला .... छत्तीसगढ़ को सक्षम प्राधिकारी .... द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र कमांक .... दिनांक .... छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के उपनियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज .... (दस्तावेज का विवरण) के प्रकाश में तथा इस समिति के द्वारा की गई जाँच एवं संतुष्टि के उपरांत सत्यापित किया जाता है :

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0 / पति .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़) की जाति / जनजाति .... संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति है जो मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 की तृतीय अनुसूची में अनुक्रमांक .... में अंकित है।

अन्वेषण अधिकारी जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	जाँचकर्ता अधिकारी,/सदस्य जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़

प्ररूप 4 घ (2)

[नियम 17 (1) देखिये]

क्रमांक .... दिनांक ....

सत्यापन प्रमाण–पत्र
(अनुसूचित जनजाति के लिए)

(हल्के गुलाबी रंग के कागज में)

श्री / श्रीमती / कुमारी ....आत्मज / आत्मजा श्री.. निवासी ....तहसील.................. जिला ....छत्तीसगढ़ को सक्षम प्राधिकारी .... द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र क्रमांक ....दिनांक .... छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के उपनियम (5) में यथा अपेक्षित दस्तावेज .... (दस्तावेज का विवरण) के प्रकाश में तथा इस समिति के द्वारा की गई जाँच एवं संतुष्टि के उपरांत सत्यापित किया जाता है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0, जाति .... निवासी.......................ग्राम .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़) की जनजाति ....संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जन जाति है जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 20 की तृतीय अनुसूची के अनुक्रमांक ....में अंकित है।

अन्वेषण अधिकारी जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	जाँचकर्ता अधिकारी / सदस्य जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़

प्ररूप 4 घ (3)

(नियम 17 (1) देखियें)

क्रमांक ____________ दिनांक ....

सत्यापन प्रमाण–पत्र
(अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)

(हल्के पीले रंग के कागज में)

श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा श्री................................ निवासी ....तहसील................ जिला .... छत्तीसगढ़ को सक्षम प्राधिकारी .... द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र कमांक .... दिनांक .... छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के उपनियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज .... (दस्तावेज का विवरण) के प्रकाश में तथा इस समिति के द्वारा की गई जॉंच एवं संतुष्टि के उपरांत सत्यापित किया जाता है।

2– श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0 / पति .... निवासी...................... ग्राम .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़) की जाति / जनजाति .... पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समय–समय पर पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं के द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–3–5 / 25 / 4 / 84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक .... पर अंकित है।

3– सत्यापित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

सतर्कता अधिकारी जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	जॉंचकर्ता अधिकारी / सदस्य जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला ....छत्तीसगढ़

प्रारूप 5 क
(नियम 4 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र के पंजीकरण **हेतु पंजी का प्रारूप**

क्र	प्रकरण क्रमांक	आवेदन प्राप्ति दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	**जाति जिसका दावा किया गया है**	**स्थाई प्रमाण–पत्र जारी दिनांक**
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**

प्रारूप 5 ख
(नियम 10 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र हेतु **प्राप्त आवेदन पत्र के पंजीयन** एवं अग्रेषण हेतु पंजी का प्रारूप

क्र	प्रकरण क्रमांक	आवेदन प्राप्ति दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	जाति जिसका दावा किया गया है	**अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी दिनांक**	**स्थाई प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषण** दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	**8**	**9**

प्रारूप 5 ग
(नियम 13 देखिये)

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र अभिलेख के पंजीयन हेतु **पंजी का प्रारूप**

क्र.	प्रकरण क्रमांक, पुस्तक क्रमांक और प्रमाण–पत्र क्रमांक	प्रमाण–पत्र जारी करने का दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	किस जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है	**संलग्न दस्तावेजों** का विवरण	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 5 घ
(नियम 16 देखिये)

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के पंजीयन हेतु पंजी का प्ररूप

क्र.	प्रकरण क्रमांक	आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख	अनावेदक का नाम एवं विवरण	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 5 ड.
[नियम 17 (2) देखिये]

सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेजों का पंजीयन हेतु प्ररूप

क्र.	प्रकरण क्रमांक, पुस्तक क्रमांक और प्रमाणपत्र क्रमांक	प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	किस जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 5 च
[नियम 18 (2) देखिये]

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के द्वारा अग्रिम जॉच हेतु छानबीन समिति को अग्रेषित आवेदन पत्र के वैवरण के लिए पंजीयन हेतु प्ररूप

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम तथा पता, जिसका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण जॉच एवं छानबीन हेतु छानबीन समिति को अग्रेषित किया गया है	उक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम एवं पता	अग्रेषित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक	छानबीन समिति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप 5 छ
(नियम 19 देखियें)

छानबीन समिति द्वारा प्रकरण के पंजीयन हेतु प्ररूप

क	प्रकरण कमांक	आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने का दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप 5 ज
[नियम 20 (7) देखिये]

पुलिस निरीक्षकों (सतर्कता प्रकोष्ठ) के द्वारा छानबीन समिति से प्राप्त प्रकरणों की जॉच–पड़ताल का विवरण
(प्रत्येक प्रकरण के लिए पंजी के पृथक पृष्ठ का उपयोग किया जावे)

क.	प्रकरण कमांक/आवेद क जिसके प्रमाण पत्र की जॉच की जानी है, का नाम/पिता का नाम/ वर्तमान पता	शिकायतकर्ता, यदि कोई हो का नाम/पिता का नाम/ वर्तमान पता	प्रकरण प्राप्त होने का दिनांक	पुलिस निरीक्षक/ निरीक्षकों के नाम जिसे जॉच सौपी गई है	जॉच हेतु प्रकरण सौपे जाने का दिनांक	पुलिस निरीक्षक/ निरीक्षकों के द्वारा जॉच हेतु भ्रमण पर जाने की तारीखों एवं स्थान का विवरण	पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान जिन व्यक्तियों से पूछताछ–बयान–शपथपत्र लिए गए हैं, उनके नाम, पिता का नाम पता, पद एवं अन्य विवरण एवं उक्त कार्यवाही की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान आवेदक, उसके माता–पिता, संबंधी तथा अन्य जिन जानने वालों से पूछताछ–बयान –शपथपत्र लिए गए हैं,उनके नाम, पिता का नाम पता, एवं अन्य विवरण एवं उक्त कार्यवाहियों की तारीखें	पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान परीक्षण किए गए लोक दस्तावेजों एवं प्रायवेट दस्तावेजों का विवरण	पुलिस निरीक्षक के द्वारा जॉच के दौरान जप्त किए गए लोक दस्तावेजों का विवरण	उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा फोरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ को प्रेषित दस्तावेजों का विवरण एवं प्रेषण दिनांक	फोरेंसिक तथा हस्तलिपि प्रतिवेदन प्राप्त होने का दिनांक	पुलिस निरीक्षक के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक	उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समिति को प्रेषित किए जाने का दिनांक
9	10	11	12	13	14	15

प्रारूप 5 झ

[नियम 23 (5) देखिये]

छानबीन समिति द्वारा प्रमाण पत्र के निरस्त एवं समपहृत करने संबंधी पंजीयन हेतु पंजी का प्ररूप

क्र.	प्रकरण कमांक	आवेदक का नाम/ पिता का नाम /पता जिसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त एवं समपहृत किया गया है	सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम एवं पता	सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र को निरस्त एवं समपहृत करने का कमांक व दिनांक	छानबीन समिति का आदेश कमांक / दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र 6 क
{ नियम 20 (1) देखियें }

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का कार्यालय

दिनांक ....

सरल कमांक ....

....

प्रति,

उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता प्रकोष्ठ
(सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन)
रायपुर

विषय : श्री / श्रीमती / कु...आ. / पति ....
.. निवासी ....के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन बाबत।

संदर्भ : जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ..../छत्तीसगढ़ शासन, ...
.... (प्रशासकीय विभाग का नाम) का पत्र कमांक ....दिनांक ....

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ..../छत्तीसगढ़ शासन, ...
...... (प्रशासकीय विभाग का नाम) के पत्र कमांक .... दिनांक .... द्वारा श्री
/ श्रीमती / कु0..................................आ0 / पति ....निवासी ....के सामाजिक
प्रास्थिति की जांच एवं छानबीन हेतु प्रेषित प्रकरण कमांक .... आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
यथानिर्देशित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक
प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 20 के प्रावधानों के अधीन आपसे
अनुरोध है कि स्वयं या अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस निरीक्षकों से उक्त प्रकरण की
जांच करें तथा स्पष्ट अभिमत सहित, समस्त मूल दस्तावेज गवाहों के कथन एवं शपथपत्र के साथ
प्रतिवेदन समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2— आपका यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त जांच के विवरण आप प्रकोष्ठ में उक्त नियम के प्ररूप 5ज के अनुसार पंजी में संधारित करें तथा उसकी एक प्रति इस समिति को भी भेजें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव अथवा उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

दिनांक............ ...

पृ. कमांक ....
प्रतिलिपि,
- सचिव / प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर ।
- अध्यक्ष, जिला स्तरीय सत्यापन समिति जिला ..../सचिव / प्रमुख सचिव / अपर मुख्य
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन. .... (प्रशासकीय विभाग का नाम) महानदी भवन नया रायपुर।

सदस्य सचिव अथवा उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

प्ररुप 6 ख
[नियम 22(1) देखियें]

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

कमांक .... दिनांक ....

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु0 ....
आ0 / पति ....
निवासी ....

कारण बताओ नोटिस

जिला स्तरीय सत्यापन समिति, जिला .... / छत्तीसगढ़ शासन, ... (प्रशासकीय विभाग का नाम) के पत्र कमांक .... दिनांक ....द्वारा आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जॉच एवं छानबीन हेतु इस समिति को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जॉच उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, (सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन समिति), रायपुर द्वारा की गई है। उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दावा किया गया आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत तरीके एवं कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है।

2—अतः इस समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 22 में यथानिर्धारित उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, (सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन समिति), रायपुर के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र को जप्त किए जाने का अपांतिम निर्णय लिया गया है।

3—उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, (सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन समिति), रायपुर के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन तथा अनुषांगिक गवाहों एवं दस्तावेजों की प्रतियॉ संलग्न प्रेषित है। आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं बतावे कि :—

1. क्या आप प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते हैं,
2. क्या आप एक मौखिक जॉच कराना चाहते हैं,
3. क्या आप अपनी सामाजिक प्रास्थिति की पुष्टि एवं समर्थन में कोई गवाह एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, यदि हॉ तो सूची प्रस्तुत करे।

4—आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में आपका स्पष्टीकरण निर्धारित समय में यदि इस समिति को प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जावेगा कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा तद्नुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव या उपाध्यक्ष
उच्च स्तरीय **प्रमाणीकरण** छानबीन समिति

प्ररूप 6 ग

[नियम 22 (5) देखियें]

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का कार्यालय

दिनांक ....

सरल क्रमांक ....
....

प्रति,

तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार

....

विषय : श्री /श्रीमती/कु..आ./पति .... निवासी .... के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन के बारे में डोंडी पिटवाने के द्वारा लोक सूचना बाबत।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन श्री/श्रीमती/कु...आ./पति............ ... .निवासी ....के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच एवं छानबीन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 22 में वर्णित अनुसार इस समिति के द्वारा की जा रही है।

2— श्री/श्रीमती/कु0...................................... ......आ0/पति ....निवासी ....की उक्त जॉच के संबंध में उनके वर्तमान निवास स्थान, पूर्व के निवास स्थानों तथा स्थायी निवास स्थान के कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध करना चाहे तो वे कर सकते हैं।

3— अतः श्री/श्रीमती/कु0.......................................आ0/पति .... निवासी ....की उक्त जॉच के परिप्रेक्ष्य में .... (ग्राम/मोहल्ले/क्षेत्र का नाम) में डोंडी पिटवा कर एवं लिखित सूचना चस्पा करवा कर यह आम सूचना प्रसारित करवाने का कष्ट करें कि क्षेत्र के निवासी तथा अन्य व्यक्ति जो श्री/श्रीमती/कु0...... ....की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में जानकारी रखते हैं दिनांक .... को ....बजे (समय) ....(स्थान) में समिति के समक्ष उपस्थित हो कर अपना मौखिक कथन/शपथपत्र अथवा कोई अनुषांगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव अथवा उपाध्यक्ष

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

प्ररूप 7 क
[नियम 27 (2) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी तथा आवेदन निरस्त करने के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन

नाम जिला.................................. वर्ष 20..........

क्र	उपखण्ड का नाम	माह	माह के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या	विगत माहों के लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल आवेदन पत्रों की संख्या (3 + 4)	माह के दौरान जारी जाति प्रमाण पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	जिला सत्यापन समिति को सत्यापन हेतु अग्रेषित जाति प्रमाण पत्रों की संख्या	माह के अंत में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप 7 ख
[नियम 27 (3) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र सत्यापित करने, आवेदन निरस्त करने तथा छानबीन समिति को अग्रेषित करने के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम .... वर्ष 20......

क.	माह	अनुविभागीय अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रमाण पत्रों की संख्या	अनावेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों/शिकायत पत्रों की संख्या	विगत माहों के लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल आवेदन पत्रों की संख्या (3 + 4)	माह के दौरान सत्यापित प्रमाण पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	छानबीन समिति को अग्रेषित, आवेदनों की संख्या	माह अंत में लंबित आवेदन पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप [illegible]
[नियम 27 (4) [illegible]]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र तथा उनके संबंध में प्राप्त [illegible] पत्रों के [illegible] प्रतिवेदन

जिला का नाम .... वर्ष 20......

क.	माह	माह के दौरान [illegible] की संख्या	सत्यापन समितियों से प्राप्त प्रकरणों की संख्या	विगत माहों के लंबित प्रकरणों की संख्या	[illegible]	माह के दौरान [illegible]	प्रकरण [illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 13–23/2012/आ. प्र./1–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13–23/2012/आ. प्र./1–3, दिनांक 2 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव,

New Raipur, the 2nd September 2013

NOTIFICATION

No. F 13-23/2012/R.C./1-3.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 ((No. 13 of 2013), the State Government, hereby makes the following Rules, namely: -

RULES

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short Title and Commencement.-** (1)These rules shall be called the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 (No. 13 of 2013);

(b) "**Applicant**" means a person, applying for Certificate in prescribed manner, verification of Certificate, a person whose Certificate is to be verified as decided by the District Level Certificates Verification Committee, or a person whose employer, educational institution, local authority, the Central Government or the State Government, as the case may be, has referred his Certificate to the District Level Certificate Verification Committee for verification;

(c) "**Application**" means an application under these rules;

(d) "**Certificate**" means a Social Status Certificate as defined under clause (o) of Section 2 and

issued under sub-section (1) of Section 4, of the Act;

(e) **"Date of Presidential Notification"** means with reference to Scheduled Castes notification dated 10th of August, 1950 and with reference to Scheduled Tribes notification dated 6th of September, 1950;

(f) **"Migrants from other States"** means the person migrating into the geographical area of State of Chhattisgarh from other State or Union Territory after the Date of Presidential Notification or Notification Date of Other Backward Class or who has been born after the Date of Presidential Notification or the Notification Date relating to Other Backward Class, as the case may be:

Provided that his father or legal guardian must have migrated into the geographical area of State of Chhattisgarh after the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Class, as the case may be;

(g) **"Non- Applicant"** means the employer or educational institution or local authority, the State Government or the Central Government, as the case maybe, which has referred the Certificate of Applicant to the verification committee for verification;

(h) **"Notification Date of Other Backward Classes"** means 26th of December, 1984;

(i) **"Notification of State Government regarding Other Backward Class"** means the order issued by the Governor or notified list of Other Backward Classes, in connection with State of Chhattisgarh, as amended from time to time;

(j) **"Prescribed"** means prescribed under these rules;

(k) **"Presidential Notification"** means order issued by the President under Article 341 and Article 342 of the Constitution of India with respect to the State of Chhattisgarh, and as amended by the Parliament from time to time;

(l) **"Provisional Social Status Certificate"** means a Social Status Certificate issued in **Form 4B** under Rule 19;

(m) **"Relative"** means related by blood from the side of applicant's paternal family;

(n) **"Resolution of the Gram Sabha"** means any declaration, conclusion, decision or a resolution of Gram Sabha of the village where applicant is domiciled, in connection to the social status of the applicant, so as to clear the social status of the applicant unambiguously;

(o) **"Scrutiny Committee "** means High Power Certification Scrutiny Committee constituted under sub-section (1) of Section 7 of the Act for scrutiny of Certificate;

(p) **"Verification Certificate"** means the certificate, issued by the District Level Certificates Verification Committee, validating the Certificate issued by the Competent Authority;

(q) **"Verification Committee" means** District Level Certificates Verification Committee constituted in a District **under sub-section (1)** of Section 6 of the Act for verification of Certificate issued to applicants.

(2) Words and Expression not defined in these rules shall have the same meanings as defined under the Act.

CHAPTER-II
ISSUING OF SOCIAL STATUS CERTIFICATE

3. **Application for issuance of Certificate.- (1)** The applicant in order to obtain Certificate on permanent basis, shall submit an application to the Competent Authority in **Form- 1A**.

(2) Applicant shall submit his application to the Competent Authority in person or through post or Choice Centre or a Common Service Centre.

(3) Applicant shall submit along with application following documents, namely:-

(a) An Affidavit in **Form-2A**, in original;

(b) Family tree of the applicant starting from last three generations, duly issued by the Halka Patwari;

(c) Document or self attested copy of the document verifying that his ancestors were residing in the geographical limits of the State of Chhattisgarh on or before the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Class, as the case may be;

(d) In cases where applicant is an officer/employee allocated to Chhattisgarh State Cadre or their children, in compliance, of Section 67 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No.28 of 2000), principles laid down in Para (1) and (2) of the Notification dated 23/09/2007of State Reorganization Cell. Such document or duly attested copies of documents, verifying that-

(i) ancestors of the applicant were residing in the geographical limits of the then State of Madhya Pradesh before or on the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Classes, as the case may be;

(ii) they have been allotted to Chhattisgarh State Cadre under Section 67 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No.28 of 2000).

(e) Any of the following document or self attested copy showing caste of the applicant's father or ancestor, namely:-

(I) Revenue document of ancestors (case file);

(II) Jama-Bandi (Survey) or Girdawari;

(III) State Settlement;

(IV) Document of Rights (1954);

(V) Census (1931);

(VI) Survey of Forest Department;

(VII) National Register of Citizens (1949);

(VIII) Register of Birth or Death;

(IX) Admission Register (Dakhil/Karij), in case father or ancestors were literate;

(X) Caste Certificate, issued earlier to Father, Ancestor or a relative;

(XI) Resolution passed by the Gram-Sabha regarding caste of the applicant where no documentary evidence in proof of caste is available;

(f) Income certificate of preceding year of applicant's father in case of Other Backward Class Applicant;

(g) Envelope having appropriate postage stamp and legible address.

(4) The applicant shall submit original certificates and documents, at the time of verification or whenever required, before the Competent Authority, District Level Certificate Verification Committee or Scrutiny Committee, as the case may be.

4. **Registration of Application.-** The Competent Authority on receipt of the application shall register the application in a register, prescribed in **Form 5A**

5. **Preliminary Inquiry of the Application, Receipt and Return Memo.-** (1) After registering application, the Competent Authority shall make a preliminary inquiry summarily, to ascertain whether the application is complete or not and whether document required under sub-rule (3) of Rule 3 are annexed or not. In case, the Competent Authority finds that the required document is annexed with the application, he shall, make available to the Applicant receipt prescribed in **Form-3A** and in case required documents are not annexed shall give to the Applicant a Return Memo in **Form-3B** within 7 days of the receipt of application.

(2) Counterfoil of the Receipt or Return Memo, as the case may be, shall be kept in the office of Competent Authority.

6. **Inability Memo.-** (1) An applicant belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who has applied for obtaining Certificate, inspite of adequate efforts could not get the required document under sub-rule (3) of Rule 3, may give an affidavit about his inability to submit such document in prescribed **Form-3C**, printed on the back of Return Memo.

(2) On receipt of Inability Memo, the Competent Authority shall not demand for the required document or documents under sub-rule(3) of Rule 3 and shall proceed to inquire the claim of the applicant under Rule 8:

Provided that the applicant shall present himself during such inquiry before the Competent Authority or before the inquiry officer indicated by him and shall give all necessary

assistance to ensure the presence of related persons, so as to prove his claim of social status.

7. **Inquiry Officer.-** Competent Officer, within fifteen days from the date of receipt of such application shall either proceed to inquire himself or shall direct a subordinate Revenue Officer for Inquiry.

8 **Inquiry.-** (1) The Inquiry Officer, shall inquire about the residence, permanent address, revenue records, immovable property, occupation of applicant's family, name in voter list and other evidence, which are relevant to prove the permanent residence on the Date of Presidential Notification or Notification Date relating to Other Backward Classes, as the case may be, and shall verify the social status claimed by the Applicant.

(2) The Competent Authority may, apart from documents mentioned in sub-rule (3) of Rule 3, inquire into documents of local bodies, for example, of Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, Nagar Panchayat, Municipality and Municipal Corporation also.

(3) Inquiry officer may also record oral statements, as evidence, of village Kotwar, village Sarpanch, Halka Patwari, local ward member, other public representatives of the area, gazetted officers residing in the locality, other local members of that caste already having Certificate and knowing the applicant properly.

(4) Inquiry officer, where he is not a Competent Officer, after inquiry shall furnish his written Report having clear outcome, along with documentary evidence and recorded oral statements to the Competent Authority, within fifteen days of receiving inquiry orders.

9 **Social Status Certificate-** The Competent Authority after receiving application under sub-rule (1) of Rule 3 and conducting an inquiry under Rule 8 and in case where himself is not an inquiry officer, after satisfying himself with the annexed documents and Report of the inquiry officer, within one month from the date of receipt of application, shall issue the certificate in **Form-4A(1)** to the Applicant of Scheduled Castes, in **Form- 4A(2)** to the Applicant of Scheduled Tribes and in **Form-4A(3)** to the applicant of Other Backward Classes.

10 **Provisional Certificate-** (1) For the purpose of granting admission to educational institutions upto tenth standard or for granting scholarship or stipend at such level or for such other purposes, where large numbers of Certificates are necessary and it is not feasible to issue such Certificate well in time, the Competent Authority, may issue a provisional certificate in **Form-4B** on the basis of affidavit given by the applicant in **Form-2A** within fifteen days from the date of application:

Provided that the Competent Authority shall maintain the details of provisional certificates issued in **Form-5B**.

(2) The provisional Certificate shall be valid only for a period of six months or till the date of issue of permanent Certificate, whichever is earlier.

11 **Certificate for the Applicant migrated from other State to the State of Chhattisgarh.-** In case, where the Applicant is a migrant from other States, Competent Officer shall issue a certificate in **Form-4C**, after making detailed inquiry, if necessary, through the District Magistrate or Verification Committee or through Vigilance Cell, regarding his social status in that State:

Provided that such certificate holder shall be eligible to avail the facilities provided to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be, in that State from which he has migrated.

12 **Involuntary Migration.-** Government employees of undivided Madhya Pradesh and such other officers and employees of Corporation, Commission, Board and Public Undertakings, who have been allocated to the State of Chhattisgarh due to division of cadres between State of Madhya Pradesh and State of Chhattisgarh under Madhya Pradesh Reorganization Act. 2000 (No.28 of 2000) such employee and his family members, if they belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes in the State of Chhattisgarh shall be deemed to have been migrated involuntary from the State of Madhya Pradesh to the State of Chhattisgarh and they shall be issued Certificate and [illegible] benefits of reservation in the State of Chhattisgarh.

13 **Certificate management register-** Details of Certificate issued by the Competent Authority shall be [illegible].

CHAPTER -III
VERIFICATION OF CERTIFICATE

14 **Constitution of District Level Certificates Verification Committee-** (1) the State Government shall constitute District Level Certificates Verification Committee having jurisdiction over one or more districts, for the verification of certificates issued by the Competent Authority, as under:-

(a) Additional Collector or Deputy Collector posted at District Headquarter, nominated by Collector;	Chairman
(b) One Officer not below the rank of class II, belonging to Scheduled Tribe, nominated by Collector;	Member
(c) One Officer not below the rank of class II, belonging to Scheduled Caste, nominated by Collector;	Member
(d) One Officer not below the rank of class II, belonging to Other Backward Class, nominated by Collector;	Member
(e) A subject expert officer or Class III executive employee, nominated by Director, Tribal Research and Training Institute;	Member

(f) Assistant Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department. — Member Secretary

(2) In case on the post of Subject Expert Officer or Class III executive employee, an appropriate officer or employee is not available for the Verification Committee then the Director, Tribal Research and Training Centre Institute, Raipur may appoint any retired officer or a Class III executive employee as member.

(3) For the nominated retired Subject Expert Officer or Class III executive employee in the Verification Committee, honorarium shall be determined by the State Government.

(4) Meetings of the Verification Committee, as required shall be held on a fixed day, every week:

But the meeting of the Committee may also be convened on the direction of Chairman with a short notice of one day.

15 **Verification of Certificate and reference to Verification Committee.-** (1) If the concerned public employer, educational institution or a statutory body the State Government or the Central Government, [illegible] raises a doubt that the person applicant admitted, [illegible] or nominated [illegible] Certificate wrongly or fraudulently then he shall ask [illegible] affidavit in Form-[illegible] and shall refer the matter to the Verification Committee [illegible].

(2) Verification [illegible] the total number of Certificates issued by the Competent [illegible] sampling method. The Applicant shall not be at liberty to seek information from the Verification Committee as to why his certificate has been selected for verification.

(3) Verification Committee may direct any Applicant to submit application in **Form-1C** along with affidavit in **Form-2C** and shall exhibit [illegible] document as required under **sub-rule (3) of Rule 3**, necessary to verify his social status.

(4) A Non-Applicant, instead of referring a certificate to the Verification Committee may also direct the Applicant to get his certificate verified by the Verification Committee. **In such cases the Applicant shall submit his original certificate, an application in Form-1C along with affidavit in Form-2C** and document as required under sub-rule (3) of Rule 3.

(5) In case of direction from Verification Committee under sub-rule (3) or direction from Non-Applicant under sub-rule 4 to verifying Certificate from the Verification Committee, the Applicant shall be bound to submit the application as mentioned above along with affidavit and documents as required under sub-rule (3) of Rule 3 within a period of not more than a month,

failing which the committee may decide ex-parte and Certificate of such Applicant shall be forwarded under Rule 18 to Scrutiny Committee:

Provided that where applicant satisfies the Verification Committee that application, affidavit and other documents could not be submitted within prescribed time limit of one month, due to adequate reasons, the Verification Committee may extend the time for the verification of certificate of the applicant.

16 **Registration of application by the Verification Committee.**- (1) Verification Committee shall register the applications for verification received from Applicant or Non-Applicant in a register as prescribed in the **Form-5D**.

(2) Verification Committee shall send receipt in **Form**-3D to the Applicant or Non-Applicant, as the case may be, within 7 days of the receipt of application.

17 **Verification of Certificate by Verification Committee.**-(1) The Verification Committee on being satisfied with the application and documentary evidence annexed therewith shall issue verification certificate in **Form-4D(1)** to Scheduled Castes, in **Form-4D**(2) to Scheduled Tribes and in **Form-4D**(3) to Other Backward Classes to the Applicant, his guardian or Non-Applicant, as the case may be, within a period of not more than one month:

Provided that if the Applicant, his guardian or Non-Applicant, as the case may be, requests to send the same by post, the committee may send the same by registered post.

(2) Verification Committee shall maintain details of the verified Certificates in **Form-5E**.

18 **Procedure where Verification Committee is not satisfied with the documentary evidence.**- (1) Where the Verification Committee is not satisfied with the documentary evidence annexed with Application, it may, within fifteen days from the date of receipt of application or within fifteen days of reference by Non-Applicant shall inform the Applicant or Non-Applicant, if any, stating the reasons of non-satisfaction thereby and shall give the Applicant, an opportunity to be heard:

Provided that the Verification Committee shall complete hearings in not more than three months and in case where the Committee is of opinion that the Certificate seems to have been obtained wrongly or fraudulently it shall forward the original certificate along with relevant documents and its findings to the Scrutiny Committee for inquiry under Rule 20 and shall also inform the Applicant and Non-Applicant, if any.

(2) Verification Committee shall maintain details of forwarded certificates to the Scrutiny Committee in **Form-5F**.

Chapter IV
Inquiry, Cancellation and Forfeiture of Certificates

19 **Registration of the Cases by High Power Certification Scrutiny Committee.-** (1) The Higher Power Certification Scrutiny Committee shall register the referred cases by Verification Committee or by the State Government or by the state Government in **Form-5G**.

20 **Inquiry of the Case through Vigilance Cell. –** (1) The Scrutiny Committee shall forward the Certificate and copies of all relevant documents in cases referred to it by Verification Committee or by the State Government or any other authority in **Form-6A** to the Vigilance Cell constituted under Deputy Superintendent of Police;

(2) The Deputy Superintendent of Police through subordinate Police Inspector shall inquire into the case and inform Scrutiny Committee accordingly;

(3) Police Inspector of Vigilance Cell shall –

(a) search places of local residence, domicile and general residence of Applicant or the city, town or village of his origin before migration;

(b) ascertain the truth regarding the Social Status as claimed by the Applicant or his parents or his Guardian, as the case may be, on the basis of public documents;

(c) verify the information stated in the application submitted to Verification Committee by the Applicant on the basis of relevant public documents and reliable private documents;

(d) obtain information from Village Kotwar, Village Sarpanch, Halka Patwari, Local Ward Member, Other Public Representatives, Local Gazetted Officers, such local members already having a Certificate and who are knowing well the Applicant and if any of them agrees to record his oral statement then he shall record his statement accordingly or shall request important witnesses to give their statement on oath and in case they agree, shall obtain the affidavit accordingly and give a copy of the same to the witness concerned;

(e) give an opportunity to the Applicant himself and parents of the Applicant and shall record the statement of witnesses indicated by them or shall obtain their affidavits;

(f) if during the examination it is found that the Applicant or any other person has maliciously forged the document, after getting the photocopy of the relevant pages, seize the document with the help of local police and shall seal and send the document to Deputy Superintendent of Police of Vigilance Cell and shall a receipt and copy of the sent, to the authorities having custody of the documents;

(g) submit his report along with all documents to the Deputy Superintendent of Police after completing the investigation.

(4) Deputy Superintendent of Police, after obtaining necessary permission of the Scrutiny Committee shall send the document seized by the Police Inspector for forensic test and to handwriting expert along with appropriate noting.

(5) The Deputy Superintendent of Police shall submit the Inquiry Report containing his clear opinion regarding social status of the Applicant, along with documents received from Police Inspector and conclusions of forensic and handwriting expert to the Scrutiny Committee.

(6) The Scrutiny Committee shall examine such report and in case it finds any deficiency in the report shall revert the same to the Vigilance Cell after indicating such deficiency and may direct for inquiry on specific issues.

(7) Police Inspector and Deputy Superintendent of Police shall maintain details of above mentioned investigation of the cases in Form-5H.

21 **Action on the Report of Vigilance Cell-** (1) If in the Inquiry Report of Vigilance Cell, claims regarding social status of the Applicant has been reported as just and proper then there shall be no further action needed by the Scruting Committee and it shall intimate accordingly to the concerned Verification Committee or the State Government, as the case may be, and to the Applicant.

(2) If the matter is referred by the State Government, the case shall be filed/closed at the State Government level with intimation to the Applicant and if the matter has been referred by the Verification Committee, then the Verification Committee after due verification in the manner provided under Rule 17 shall send the Original and Verified Certificate to the Applicant or Non-Applicant, as the case may be.

22 **Inquiry by High Power Certification Scrutiny Committee-** (1) Where the Scrutiny Committee is not satisfied with the social status claim of the Applicant, according to the inquiry Report of the Vigilance Cell the committee may through registered post shall issue a show-cause notice to Applicant in prescribed **Form-6B** along with report of the Vigilance Cell and the copy of such notice shall also be given to the Non-Applicant (if any) also.

(2) After on receiving the reply of the Applicant, the Scrutiny Committee shall convene a meeting wherein it shall direct the Applicant to produce his/her Certificate in original and Applicant shall be given adequate opportunity of hearing and producing evidence.

(3) The Scrutiny Committee shall also issue a public notice regarding the hearing, which shall be widely publicized in the village or announced by beat of drum, advertisement or through some other convenient means, so that any person or institution may support or oppose the applicant's claim and such person or institution shall also be accorded an opportunity of hearing and producing evidence, if any.

(4) After giving reasonable opportunity of hearing to the Applicant or to his guardian (in case the applicant is not an adult), Scrutiny Committee may conduct such inquiry, so as to consider the claim and other objections.

(5) Scrutiny Committee may send the notice or summons for service to the Tehsildar, Additional Tehsildar, Nayab Tehsildar, who shall serve the notice in the manner as directed in **Form-6C.**

23 **Decision of the Scrutiny Committee and proceedings thereafter.– (1)** After hearing both the sides in support and against the claim, the Scrutiny Committee on being satisfied with regarding the genuineness of the claim of the Applicant shall direct the concerned Verification Committee to issue Verification Certificate, if applied so.

(2) If after hearing the Applicant regarding his claim of Social Status Certificate the Scrutiny Committee, comes to the conclusion that the claim of the Applicant is not genuine, it may pass a reasoned order and cancel the Certificate

(3) The Scrutiny Committee while passing order under sub-rule (2) shall authorise an officer of the employer, educational institution, local authority, the Central Government or the State Government to file complaint under sub-section (2) of section 10 of the Act and forward attested copies of all documents related to the case to such officer for further proceedings.

(4) The Scrutiny Committee while passing order under sub-rule (2) of this Rule shall issue instruction to the concerned Collector to investigate, whether the the Competent Authority knowingly or having knowledge that such certificate was false has issued such False Social Status Certificate or any other person has abetted such offence and the Collector shall forward his report to the State Government, within three months.

(5) The Scrutiny Committee after passing the order of cancellation of False Social Status Certificate shall confiscate it and details shall be entered in the register as prescribed in **Form-5I** and such Certificate shall be impressed as "Cancelled and Confiscated".

(6) Copies of the order passed by the Scrutiny Committee shall be sent to the Non-Applicant, if any, and to the Applicant by registered post immediately after passing such order. If the Applicant or any other person present in the office demands copy of the order, the same shall be supplied to the person on payment of appropriate fee.

24 **Action against false Certificate holder.-** The officer of the public employer, educational institution or a statutory body, the State Government or Central Government as the case may be, who is authorised by the Scrutiny Committee shall on the basis of the attested copy of the decision passed by the Scrutiny Committee, shall file a written complaint in the Police Station under sub-section (1) of Section 154 of Criminal Procedure Code, 1973 (Act no.2 of 1974) against the said False Social Status Certificate holder.

25 **Action against the abettor and Competent Authority issuing False Social Status Certificate.-** The Collector of the concerned district shall file written complaint against the Competent Authority issuing False Social Status Certificate and the abettor of the offence.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

26 **Procedure for issuing duplicate of Certificate and Verification Certificate-** Where an original certificate or verification certificate relating to an Applicant has been lost or stolen or destroyed due to natural calamities like floods, earthquake etc or on request and after depositing fee as prescribed by the State Government, Competent Authority or Verification Committee as the case may be, may issue the duplicate on the basis of original document kept in such office. There shall be a clear mention of "Duplicate Copy" on such Certificate or Verification Certificate.

27 **Notice regarding Issuance, Verification or Cancellation of Certificate-** (1) Competent Authority, Verification Committee and Scrutiny Committee, as the case may be, shall display the information regarding issuance, verification or cancellation of Certificate every month, before the Fifth day of the month on the office Notice Board and shall also send the information to local autonomous institutions and bodies, municipal corporation, municipality, village panchayat etc. for their records and shall also send the information through District Information Centres, in order to display it on ascertained website.

(2) Competent Authority shall also send the information regarding issue of certificate and cancellation of applications, every year by 31st December to the State Government, in prescribed **Form-7A.**

(3) Verification Committee shall send the information regarding verification of certificates, cancellation of application, cases forwarded to Scrutiny Committee every year by 31st December to the State Government, in prescribed **Form- 7B.**

(4) Scrutiny Committee shall send the information regarding inquiry on the complaints referred by the State Government and Verification Committees and cancellation of Certificate, every year by 31st December to the State Government in prescribed **Form-7C.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

Form- 1A
(See Rule 3(1))
Application For Social Status Certificate

To,

Competent Authority,

Sub-Division..... District.....

Sir,

I beg to state that in order to avail facilities given to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes, I/ my son/daughter requires Certificate of Social Status. In this connection following information is being submitted, namely:-

1 Name of the Applicant

2 Father's Name of the Applicant

3 Applicant's marital status: Married/Unmarried

4 Name of the Husband (in case of female applicant)

5 Date of Birth of Applicant

6 Caste (For SC only)

7 Present Address in full: Mohalla/Ward
Village/Town/City.....
Block..... Tehsil.....
District.....
State.....

8 Permanent Address in full: Mohalla/Ward
Village/Town/City.....
Block..... Tehsil.....
District.....
State.....

9 Applicant's Date of Birth:
(a) if before 10/08/50 for SC and 6/9/50 for ST;
(b) if before 26/12/84 for OBC
then, place of birth of applicant; or if after these dates then permanent residential address of his Father/Ancestor

10 Head of the Family residing on the above-mentioned address on the above-mentioned date.
Mohalla/Ward.....
Village/Town/City.....
Block..... Tehsil.....
District..... State.....
Name.....
Relation with the Applicant.....